सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 17 JULY TO 23 JULY 2020 • VOLUME- 45 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
No Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD
CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE
E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

न्यूज

अशोकनगर के नए कलेक्टर अभय वर्मा

भोपाल, (प्रसं)। मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी अभय कुमार वर्मा को अशोकनगर जिला कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वर्ष 2007 बैच के आईएएस अधिकारी श्री वर्मा अभी तक राजभवन भोपाल में राज्यपाल के अपर सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा 2017 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार सत्यम को छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी (एसडीएम) पदस्थ किया गया है। वे अभी तक डिंडोरी जिले में एसडीएम के तौर पर कार्यरत थे।

तीन राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए

नई दिल्ली, (एजेंसी)। तीन राज्यों में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश फिर गुजरात और इसके बाद असम भूकंप के झटकों से दहल गया। हिमाचल प्रदेश में ऊना में गुरुवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह तड़के 4.47 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.3 आंकी गई। गुजरात में सुबह 7:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 आंकी गई। असम के करीमगंज में सुबह 7.57 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 आंकी गई।

कोरोना से पूर्व महिला चुनाव आयुक्त की मौत

मुंबई, (एजेंसी)। कोरोना से संक्रमित महाराष्ट्र की पहली चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण (सेवानिवृत्त) (72) का गुरुवार को यहां सेवन हिल्स अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। सुश्री सत्यनारायण 1972 बैच की आईएएस अधिकारी थी। उन्हें सख्त व निष्पक्ष अधिकारी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने शानदार करियर के दौरान महाराष्ट्र में शीर्ष पदों जैसे सचिव, प्रधान सचिव के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर सेवा दी थी। सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी ने मराठी में कई पुस्तकें लिखी। फिल्म 'जजमेंट' उनके उपन्यास रोउन्न पर आधारित थी।

मुंबई में इमारत ढही छह लोगों की मौत

मुंबई, (एजेंसी)। भारी बारिश के चलते गुरुवार को मुंबई में एक के बाद एक इमारतें ढह रही हैं। दोपहर में मलवानी इलाके में इमारत का एक हिस्सा गिर जाने से छह लोग मलबे से दब गए थे। इस बीच, शाम को भी किला क्षेत्र स्थित छह मंजिली भानुशाली इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे से कई लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान छह लोगों की मौत हो गई, 25 घायल हो गए। सीएम भी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। सबसे पहले दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में पुरानी छह मंजिला इमारत के एक कोने का हिस्सा ढह गया, जिसमें कई घायल हुए।

24 घंटे खुली रखने वाली मिनी नेस्ट रात को बंद कर देती है टोल कंपनियां

रोपड़-चंडीगढ़ के टोल पर बंद पड़ी मिनी नेस्ट

जालंधर ब्रीज ब्यूरो

नेशनल हाईवे विभाग द्वारा सड़क निर्माण करने के समय जब शर्तें निर्धारित की जाती है उसको वो जमीनी स्तर पर भ्रष्ट अधिकारी ठेका प्राप्त कम्पनियों से पूरी करवाने में विफल साबित होते है । ठेका देने के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए करोड़ों रूपये की भरपाई बाहर से रखे हुए कंसल्टैंटों को अदायिगी की जाती है परन्तु जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही ब्यान करती है आये दिन आम नागरिकों से टोल कम्पनियों द्वारा लोगों को टोल की वसूली करते समय अलग अलग तरीकों से परेशान करने की अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलती रहती है पर प्रशासन कम्पनियों के आगे बिल्कुल मौन धारे हुए देखता रहता है। कोरोना महामारी के दौर में जहाँ प्रशासन द्वारा रोड़ नए-नए कानून बनाकर लोगों से उसकी पालना करने के लिए कहा जा रहा है परन्तु जो कानून पहले से ही बनाये हुए उसकी और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा जिसका एक उदहारण आपको टोल पर मिनी नेस्ट बनाना अनिवार्य है जिसको 24 घंटे खुला रखना अनिवार्य है जिसमें चाये पानी कोल्ड्रिंक से लेकर हल्का फुल्का स्नैक्स का सामान रखना अनिवार्य है परन्तु टोल कंपनियां मुलाजिम के खर्चे को बचाने की ऐवज में इसको रात 8 बजे या 9 बजे बंद कर देती है जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

जियो का सस्ता स्मार्टफोन फोन चीनी कंपनियों के लिए होगा चुनौती

नई दिल्ली/ब्यूरो

रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भारतीय बाजार में सस्ते स्मार्टफोन फोन लाने की तैयारी कर ली है। इसमें मदद के लिए दिग्गज कंपनियों को जियो प्लेटफॉर्स के मंच पर एक साथ लाया है। जो भारतीय स्मार्टफोन बाजार में धाक जमाये बैठी चीनी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। वर्तमान माहौल में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच आए संबंधों के अत्यंत तनावपूर्ण होने से जियो का सस्ता स्मार्टफोन चीनी कंपनियों के लिए जबर्दस्त चुनौती साबित हो सकता है।

अंबानी ने अगले तीन वर्ष में रिलायंस जियो के उपभोताओं को पचास करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है करीब चार साल पहले पांच सितंबर 2016 को भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में कदम रखने वाली जियो के इस वर्ष मार्च में 38 करोड 75 लाख 16 हजार 803 ग्राहक थे और वह 33.47 प्रतिशत बाजार हिस्से के साथ पहले स्थान पर काबिज थी।

इससे पहले भी जियो के सस्ते फोन ने तहलका मचाया और इसके आने से फीचर्स फोनों का बाजार लगभग सिमट गया।

ठगी के शिकार हुए लोगों को स्टेशन हाउस अफसर द्वारा पुलिस स्टेशन नंबर 7 में सुनवाई के लिए बुलाया

जालंधर ब्रीज ब्यूरो

पुलिस कमिश्नर जालन्धर को एम. एल.एम कंपनी (ओ.एल.एस. व्हिज़ज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी) के नाम पर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से शिकायत दी गयी। जिसमें उन्होंने बताया की कंपनी के लगभग 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स है इसमें वह कई तरह की चीज़े बेचते हैं जिसमे सोना भी आता है कंपनी का मालिक रंजीत सिंह पिता का नाम गुरमीत सिंह 23-ए शिव विहार का रहने वाला है और दूसरा पार्टनर गगनदीप सिंह पिता का नाम गुरविंदर सिंह 52 हरदीप नगर जालंधर का रहने वाला है। यह दोनों अपने परिवार के साथ घर छोड़कर और कंपनी के बैंक एकाउंट्स से सारे पैसे निकाल कर गायब हो गए हैं इन्होंने अपनी कंपनी वेबसाइट से भी सारा डाटा डिलीट कर दिया है।

59 लोगों द्वारा पुलिस डिवीज़न नंबर 7 में इन दोनों के खिलाफ शिकायत दी गई

जालंधर से लगभग इनके साथ 10000 सदस्य जुड़े हुए हैं जिनका कहना है की इन्होंने कंपनी से 25 करोड़ रूपए लेने है जब वह इनके रजिस्टर्ड दफ्तर पी.पी.आर मार्किट जालंधर में गए तो वहां स्टाफ द्वारा उनसे कहा गया की मालिक क्या काम कर रहे और कहाँ है उन्हें नहीं पता तो कुल मिलकर 59 लोगों द्वारा पुलिस डिवीज़न नंबर 7 में इन दोनों के खिलाफ शिकायत दी गई और स्टेशन हाउस अफसर को इनके खिलाफ जल्द से जल्द करवाई करने के लिए कहा गया ताकि लोगों की खून पसीने की कमाई उन्हें वापिस मिल सके।

जाधव को सशर्त कॉन्सुलर एक्सेस

भारतीय अधिकारी और जाधव को अंग्रेजी में करना होगी बात

इस्लामाबाद ■ एजेंसी

पाक ने आखिरकार अपनी जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए दूसरी बार भारतीय उच्चायुक्त को सशर्त मंजूरी दी है। इसके बाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारी वकीलों के साथ विदेश मंत्रालय पहुंचे। दरअसल, पाक के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम श्री जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी थी।

अब भारतीय अधिकारी श्री जाधव की पुनर्विचार याचिका पर हस्ताक्षर करेंगे। पाक ने भारतीय उच्चायोग को दे दी है। जाधव से मुलाकात के लिए पाकिस्तान ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मुलाकात के दौरान भारतीय अधिकारी और श्री जाधव को अंग्रेजी में बात करनी होगी और पाकिस्तानी अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम कहा था कि अपील और समीक्षा याचिका को जाधव या उनके कानूनी प्रतिनिधि या इस्लामाबाद में भारत के काउंसलर अधिकारी दायर कर सकते हैं। इससे पूर्व पाकिस्तान ने कहा था कि मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी श्री जाधव ने सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करने से इनकार कर दिया है।

प्यारे मियां को भोपाल लाई एसआईटी

कोर्ट में पेश नहीं हो सका, जेपी अस्पताल में मेडिकल चेकअप

भोपाल ■ न्यूज नेटवर्क

नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी दलाल प्यारे मियां को एसआईटी की टीम गुरुवार सुबह करीब 11 बजे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल लेकर आई। कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से सीधे नए पुलिस कंट्रोल रूम लाकर प्यारे मियां से पूछताछ की गई। इस दौरान मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया।

गौरतलब है कि भोपाल पुलिस की टीम ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद से बुधवार को श्रीनगर की एक होटल से आरोपी प्यारे मियां को गिरफ्तार किया था। करीब दो घंटे तक चली पूछताछ के बाद मेडिकल जांच के लिए उसे जेपी अस्पताल ले जाया गया। जेपी अस्पताल में मेडिकल चेकअप के अलावा कोरोना परीक्षण भी किया गया।

आज होंगे कोर्ट में पेश

अदालत के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्यारे मियां को शुक्रवार सुबह करीब ग्यारह बजे भोपाल के सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जा सकता है। कोरोना के चलते जिला अदालत में सत्र न्यायालय का कामकाज सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर दो बजे तक ही होता हैं और दो बजे से पांच बजे तक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का कामकाज शुरू होता हैं। इस कारण से प्यारे मियां को शुक्रवार को सुबह 11 बजे सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश कर सकते हैं। इसके अलावा संभावना यह भी है कि पुलिस शायद जज के बंगले में प्यारे मियां को पेश कर सकती है। वैसे पुलिस के पास कोर्ट में पेश करने के लिए शुक्रवार सुबह यान 17 जुलाई तक का वक्त है।

एएमयू छात्रा को 'पीतल का हिजाब' पहनाने की धमकी पर यूपी के मंत्री का रुख सख्त

अलीगढ़ (एजेंसी)। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने अपने एक साथी छात्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस लड़के ने सोशल मीडिया पर उसे धमकी दी थी कि फिर से विश्वविद्यालय खुलने के बाद उसे पीतल का हिजाब पहनना होगा।

ऐसी मानसिकता वाले लोग तालिबान चले जाएं: मोहसिन रजा

इस पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ये देश को तोड़ने वाली शक्तियां है। जो हिंदुस्तान में बार- बार इस तरह की हरकतें करती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में उन्हें सलाह है कि जो इस तरह के राय लेकर घूम रहे हैं बेहतर होगा वह तालिबान चले जाएं। जो लोग इस तरह के अनर्गल और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगें।

बता दें इस मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने अलीगढ़ के एसपी (अपराध) अरविंद कुमार को पत्र लिखकर छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल बुलंदशहर की रहने वाली गैर मुस्लिम छात्रा का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उन्हें हिजाब (बुर्का) पहनाने की धमकी दी गई है। जिसके बाद छात्रा द्वारा एसएसपी को दी गई शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। धमकी देने वाला शख्स एएमयू छात्र बताया गया है।

राहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर तीन देशों से हो रही बात, 18 जुलाई से फ्रांस शुरू करेगा सेवा: पुरी

तीन देशों के लिए आज से शुरू होंगी उड़ानें

नई दिल्ली ■ एजेंसी

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को वंदे भारत मिशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि तीन देशों के अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरूआत शुक्रवार से शुरू हो रही है। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से बंद अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा को दोबारा शुरू करने को लेकर जानकारी दी। पुरी ने कहा कि कोविड-19 से पहले जितनी घरेलू उड़ानों का संचालन होता था उसका 55 से 60 फीसदी दीवाली तक होने लगेगा।

पुरी ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत एयर फ्रांस एयरलाइन 18 जुलाई से एक अगस्त तक दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानों का संचालन करेगी। इसके अलावा अमेरिका की एयरलाइंस की 18 उड़ानें 17 से 31 जुलाई के बीच भारत आएंगी। इसके अलावा जर्मनी की एयरलाइंस ने भी भारत के लिए उड़ानें संचालित करने की अनुमति मांगी है। इस पर काम जारी है।

बता दें कि देश में कोरोना के चलते 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वंदे भारत मिशन को लेकर पुरी ने कहा कि अब तक दो लाख 80 हजार भारतीयों को विदेशों से वापस लाया गया है। दुबई और यूएई से बड़ी संख्या में भारतीय को स्वदेश लाया गया। वहीं, अमेरिका से 30 हजार भारतीयों को इस मिशन के तहत वापस लाया गया है।

कोरोना से संकट में एयर इंडिया

हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एयर इंडिया का निजीकरण जरूरी है, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि विदाउट पे कर्मचारियों को लीव पर सभी एयरलाइंस कंपनियां भेज रही हैं, क्योंकि यह उनकी मजबूरी है। सरकार उस स्थिति में नहीं है कि एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी आर्थिक मदद कर सके। वहीं एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से एयरलाइंस को भारी नुकसान हो रहा है। खर्च कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से एक कर्मचारियों की संख्या में कटौती भी है। कंपनी अपने कुछ कर्मचारियों के पोस्ट रिटायरमेंट पर भी विचार कर रही है।

दखल

संरक्षणवाद से उपजा संकट

इस वर्ष मई में कुवैत सरकार ने नगरपालिका की सभी नौकरियों में प्रवासियों की जगह कुवैत के नागरिकों को नियुक्त करने को कहा था और अगले ही महीने यानी जून में सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (केपीसी) और इसकी इकाइयों में 2020-21 के लिए सभी प्रवासियों को प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी गई। यह प्रस्ताव किसी भी दृष्टि से सही नहीं है।

रोजगार की अनिश्चितताओं व तेल की गिरती कीमतों, जनता की सुविधाओं के ध्यान, महामारी के नकारात्मक प्रभावों और वैश्विक और क्षेत्रीय मंदी की आशंकाओं के बीच खाड़ी देश कुवैत ने एक बड़ा संरक्षणवादी कदम उठाया है। इससे कुवैत में रहने वाले प्रवासी भारतीयों और साथ ही उनके द्वारा वहां से भेजे जाने वाले धन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कोरोना महामारी के बीच कुवैत ने अपनी संसद में एक कानून पारित कर प्रावधान किया है कि अब भारतीय प्रवासी यहां की कुल आबादी के 15 फीसद से अधिक नहीं हो सकते। इसके चलते कुवैत में रह रहे भारतीयों में से आठ लाख भारतीयों पर चिंता और आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। कुवैत की नेशनल असेंबली की विधायी समिति ने संबंधित विधेयक को संवैधानिक करार दिया है। गौरतलब है कि कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है। इसमें से 30 लाख विदेशी या प्रवासी हैं। कुवैत में लगभग साढ़े चौदह लाख भारतीय रहते हैं और अब इस कानून से आठ लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। कुवैत की स्थानीय जनसंख्या को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।

कुवैत में संरक्षणवादी नीतियों के हालिया उभार की बात करें तो पता चलेगा कि वहां के सांसदों से कहा गया है कि एक साल के अंदर सभी सरकारी विभागों से प्रवासियों की नौकरियां खत्म करने संबंधी दिशा में काम शुरू कर दें। इसी वर्ष मई में कुवैत सरकार ने नगरपालिका की सभी नौकरियों में प्रवासियों की जगह कुवैत के नागरिकों को नियुक्त करने को कहा था और अगले ही महीने यानी जून में सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (केपीसी) और इसकी इकाइयों में 2020-21 के लिए सभी प्रवासियों को प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी गई। वर्तमान में यहां दूसरे देशों के लोगों को नौकरियां देने पर भी रोक है। गौरतलब है कि कुवैत भारत के लिए विदेशों से भेजे जाने वाले धन का एक शीर्ष स्रोत भी है। वर्ष 2018 में कुवैत में रह रहे भारतीयों ने भारत में 4.8 अरब डॉलर की रकम भेजी थी। कुवैत भारत के शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों में भी शामिल है। वर्ष 2015-16 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार 6.2 अरब डॉलर था।

कुवैत में भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस से भी बड़ी संख्या में प्रवासी काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही कुवैत सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय को आश्वस्त करते हुए कहा था कि वह भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की असुरक्षा पर कुछ ना कह कर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति का पालन करेगा। भारत ने कोविड-19 से निपटने में कुवैत को चिकित्सा सहायता करने में सक्रियता दिखाई थी। इसके अलावा खाड़ी देश ओमान ने भी अपने यहां सरकारी नौकरियों में ओमान के नागरिकों की ही भर्ती करने और उन्हें प्राथमिकता देने की घोषणा कर दी। यद्यपि इस तरह के कदम वैश्वीकरण और मुक्त प्रतिस्पर्द्धा को नकारने जैसे हैं, लेकिन अपने स्वदेशी नागरिकों को तरजीह देने को सभी देश औचित्यपूर्ण ठहराने लगे हैं। ओमान में सात लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें से छह लाख शुद्ध रूप से श्रमिक और पेशेवर वर्ग के हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग और इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट को देखें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीय प्रवासियों का है। इनके अनुसार कामगार भारतीयों की संख्या एक करोड़ साठ लाख से एक करोड़ 70 लाख के बीच है।

वहीं यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, 2018 में बताया गया है कि प्रवासी भारतीय कामगारों की संख्या एक करोड़ 56 लाख है। जाहिर है, प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने देश को भेजे जाने वाली विदेशी मुद्रा भी कम नहीं है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2018 में प्रवासी भारतीयों ने अस्सी अरब डॉलर का देश में भेजे। यूएई में अकेले लगभग 35 लाख भारतीय कार्यरत हैं। सऊदी अरब में 25 लाख, ओमान और कुवैत दोनों में 14 लाख प्रवासी भारतीय कार्यरत हैं। ऐसे में इनकों मिलने वाली सुविधाएं और इनकी सुरक्षा का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों केरल, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र से खाड़ी देशों में सस्ते श्रमिक के रूप में काम करने के लिए जाने वाले भारतीयों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मसलन वीजा, पासपोर्ट की औपचारिकताएं, विदेश में इसकी जब्ती, नस्लीय भेदभाव, जासूसी के आरोप, आतंकी नेटवर्क में संलग्नता के आरोप, मालिकों द्वारा उचित मजदूरी न देना, निर्धारित अवधि से कई ज्यादा घंटे काम लेना, स्वदेश वापसी में अड़चनें पैदा करना। गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, शरणार्थी संकट की स्थिति में भी कामगारों के समक्ष समस्याएं बढ़ जाती हैं।

अरब विश्व के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। लेकिन खाड़ी देशों, मध्य पूर्व अथवा पश्चिम एशिया के इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंधों में समय-समय पर उतार-चढ़ाव भी देखे गए हैं। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने जहां खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंधों पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से उपजे विरोध-प्रदर्शन, दंगे और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों के प्रश्नों पर कई इस्लामिक देशों सहित खाड़ी देशों में असंतोष की लहर देखने को मिली। इससे नाराज कुछ खाड़ी देशों जैसे कुवैत ने इस्लामिक सहयोग संगठन से यहां तक मांग तक कर दी कि भारत में मुसलिम अल्पसंख्यक समुदाय के संरक्षण के मामले को उसे संज्ञान में लेना चाहिए। दिल्ली में तब्लीगी जमात के खिलाफ कार्रवाई पर पर भी कई इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ आवाज उठाई। इन प्रकरणों से भारत विरोधी जिस मानसिकता को खाड़ी देशों में हवा मिली थी, उसकी गति को तेज करने का काम कोविड 19 महामारी ने कर दिया, क्योंकि इसने खाड़ी देशों को भारत सहित कई देशों के खिलाफ संरक्षणवादी नीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त अरब अमीरात में कई भारतीयों को सोशल मीडिया पर मुस्लिम विरोधी पोस्ट और कोरोना जेहाद के सिद्धांत गढ़ने के आरोपों के चलते नौकरियों से हाथ धोना पड़ गया।

विश्व बैंक ने कोरोना आपदा में वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक विकास की गतिशीलता के वाहक और महत्वपूर्ण उपकरण-वित्त प्रेषण (प्रवासियों द्वारा अपने देशों में पैसा भेजने) पर आ रहे नकारात्मक प्रभावों की पहचान की है। इसमें कहा गया है कि हाल के इतिहास में वित्त प्रेषण में इतनी तेज गिरावट कभी नहीं आई, जितनी कि कोरोना महामारी के दौरान आई है। विश्व बैंक के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से दुनियाभर में आर्थिक संकट गहराया है और इस वजह से प्रवासियों के धन प्रेषण में 20 फीसद से ज्यादा की गिरावट की संभावना है। भारत में यह गिरावट 23 फीसद तक जा सकती है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों से ही मिलती रही है जो पिछले कुछ वर्षों में 35 से 40 अरब डॉलर के बीच रही है। भारत को खाड़ी देशों को विश्वास में लेने की जरूरत है, ताकि भारतीयों के हितों को चोट न पहुंचे। इसके लिए खाड़ी देशों के समक्ष भी कुछ लाभदायक प्रस्ताव रखने पड़ेंगे, ताकि खाड़ी में काम कर रहे लाखों भारतीयों पर स्वदेश वापसी का संकट खड़ा न हो।

कुवैत से प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब पूरी दुनिया में रोजगार को लेकर मारामारी मची है। अगर अभी कुवैत से आठ लाख भारतीय स्वदेश वापस आते हैं तो यह संकट को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि तत्काल इनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए आसान नहीं है।

विचार

कोरोना अब बढ़ा रहा चिंता

कोरोना से बचाव के टीके को लेकर कई देशों में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन इस मामले में सावधानी की जरूरत है। इतना तय है कि लंबे समय तक अगर यह स्थिति बनी रही तो कई देश आर्थिक व स्वास्थ्य सहित कई स्तरों पर बहुत कठिन चुनौतियों से घिर जाएंगे।

पिछले पांच-छह महीने की तमाम कवायदों के बावजूद अब भी अगर कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है तो यह चिंता की बात है। हालत यह है कि कोरोना से जंग में इतनी जद्दोजहद के बाद आज भी डब्ल्यूएचओ स्थिति और खराब होने की आशंका जता रहा है। इस चिंता का आधार यह है कि दुनिया के कई देश कोरोना से निपटने के मामले में गलत दिशा में जा रहे हैं। इस वजह से संक्रमित लोगों और मरने वालों की तादाद में और बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को कोरोना के नए मामलों ने फिर रिकॉर्ड बनाया। पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के 32695 नए मामले सामने आए। देश में लगातार सातवें दिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 26,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमण के मामले 9,68,876 हो गए जिनमें से 3,31,146 लोगों का उपचार चल रहा है और 6,12,815 लोग मुक्त हो चुके हैं।

डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जिन एहतियात और उपायों की बात की जा रही है, उनका पालन नहीं किया जा रहा है; अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह महामारी बद से बदतर होती जाएगी। यह समझा जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ की चिंता विश्व भर में कोरोना के फैलते पांव के मद्देनजर है और इसके आकलन के मजबूत आधार होंगे। मगर सवाल है कि आखिर किन वजहों से कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती उपाय करने में कुछ देश लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि शुरुआत में डब्ल्यूएचओ के निर्देशों के मुताबिक दुनिया भर में अलग-अलग देशों में इससे बचाव के लिए जिस तरह के कदम उठाए गए, उससे इस महामारी पर काबू पाने की उम्मीद की गई थी। लेकिन इस बीमारी से संक्रमित लोगों और मरने वालों के जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि या तो इससे बचाव के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों पर अमल में कोताही बरती जा रही है या फिर यह बीमारी पर काबू पाना संभव नहीं हो पा रहा है। कोरोना से बचाव का अब तक कोई चिकित्सकीय उपाय नहीं निकल पाया है, इसलिए फिलहाल इससे बचाव ही रास्ता है और यह कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मसलन, डब्ल्यूएचओ ने दिशा-निर्देश में लोगों के बीच आपस में थोड़ी दूरी बरतने, हाथ धोने और मास्क पहनने जैसे बहुत साधारण उपायों को शामिल किया है, जिससे संक्रमण को रोका जा सकता है। लेकिन अफसोस है कि सिर्फ इतने उपाय करने में भी कुछ देशों में कोताही बरती जा रही है। जबकि इस वायरस के बारे में जैसे अध्ययन सामने आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि निकट भविष्य में पहले की तरह सब कुछ सामान्य नहीं हो पाएगा। कोरोना से बचाव के टीके को लेकर कई देशों में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन इस मामले में बहुत सावधानी बरते जाने की जरूरत है। इतना तय है कि लंबे समय तक अगर यह स्थिति बनी रही तो बहुत सारे देश कई स्तरों पर बहुत कठिन चुनौतियों से घिर जाएंगे।

डॉक्टरों की नहीं प्रबंधन की कमी

डॉक्टर-मरीज का अनुपात मानक एक हजार तय है यानी हजार लोगों पर एक डॉक्टर। लेकिन हमारे यहां यह अनुपात बेमानी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो यह आंकड़ा और भी कम हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में डॉक्टरों की तादाद पहले से ही ज्यादा है, उस पर नए डॉक्टर भी शहरों में ही काम करना पसंद करते हैं। ज्यादातर युवा डॉक्टर संपन्न परिवारों से आते हैं और गांवों को लेकर उनके मन में कई पूर्वाग्रह होते हैं।

देश में डॉक्टरों की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट पेश की है जिसके अनुसार 1,445 लोगों की जिम्मेदारी केवल एक एलोपैथ के डॉक्टर के कंधों पर है। उत्तर भारत में सबसे बुरे हालात हरियाणा में हैं। यहां एक एलोपैथी डॉक्टर पर 6,287 लोगों की जिम्मेदारी है। जबकि उत्तर प्रदेश में 3,692, उत्तराखंड में 1,631, पंजाब में 778, हिमाचल प्रदेश में 3,015, जम्मू कश्मीर में 1,143 और दिल्ली में 1,252 लोगों के लिए एक एलोपैथी डॉक्टर पंजीकृत हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 11.59 लाख एलोपैथी के डॉक्टर पंजीकृत हैं लेकिन इनमें से 9.27 लाख डॉक्टर ही हर दिन अस्पताल या क्लीनिक में मरीज का उपचार कर रहे हैं। चूंकि देश की आबादी 1.35 बिलियन है, इस हिसाब से देश में 1,445 लोगों की आबादी पर एक एलोपैथी डॉक्टर मौजूद है। हालांकि मंत्रालय का यह भी मानना है कि देश में मरीजों की तादाद हर साल बढ़ रही है। ऐसे में सभी चिकित्सा पद्धतियों के तहत आने वाले डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना बेहद आवश्यक है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से गांव इन दिनों सबसे ज्यादा घाटे में हैं। शहरों में तो फिर भी सुविधाओं का लाभ मिल जाता है, मगर गांवों में स्थितियां बदतर हैं। फिर सरकारी आंकड़े कुछ भी हों लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। ग्रामीणों को अपनी छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए शहरों की ओर दौड़ना पड़ता है। इसमें उन्हें समय का तो नुकसान होता ही है, निजी अस्पतालों के महंगे इलाज का भी शिकार होना पड़ता है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों का धंधा भी तेजी से फल-फूल रहा है। हमारे देश की 70 फीसद से ज्यादा आबादी गांव में रहती है पर इलाज के लिए कई-कई किलोमीटर दूर चल कर ग्रामीणों को अस्पताल जाना पड़ता है।

कहीं-कहीं तो उन्हें 50 से 100 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। कई गांवों के बीच एक स्वास्थ्य केंद्र है भी तो जरूरी नहीं कि वहां इलाज हो जाएगा। ज्यादातर को इलाज की जगह निराशा ही हाथ लगती है। केंद्र और राज्य सरकारें हर साल अपने बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बड़ा हिस्सा रखती हैं मगर इसका असर गांवों में नजर ही नहीं आता है। कहीं भवन नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं। कहीं दवाइयां नहीं तो कहीं सुविधाएं नहीं। सरकारों ने देश में बड़ी तादाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। इनमें कर्मचारी भी तैनात किए हैं। फिर भी डॉक्टरों और मैदानी स्वास्थ्य अमले की कमी से ग्रामीणों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। सो, मजबूरन उन्हें झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाना पड़ता है। देश में अब भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों की दस से बीस फीसद ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच है। दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में यह स्थिति और भी बदतर है। कमोबेश यही स्थिति रेफरल अस्पतालों की भी है। फिलहाल करीब 12 सौ लोगों पर एक बिस्तर है, जबकि मानक रूप से यह पांच सौ लोगों पर होना चाहिए। इनमें भी ज्यादातर शहरों या फिर शहरों के आसपास ही हैं। अकेला केरल ऐसा राज्य है जहां अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में ये कम हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में दवाइयों और उपकरणों की कमी भी इन सेवाओं को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण है। स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा डॉक्टरों और अमले के वेतन-भत्तों पर ही खर्च हो जाता है। वेतन-भत्तों में कभी कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए कटौती दवाइयों व उपकरणों की खरीद, भवन और वाहनों में की जाती है। 'सबके लिए स्वास्थ्य' नामक रिपोर्ट कहती है कि देश में स्वास्थ्य खर्च का अधिकांश हिस्सा शहरी आबादी के लिए हो जाता है और इससे समाज का बीस से तीस फीसद वर्ग ही लाभान्वित हो पाता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करीब एक लाख लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करता है और प्रति केंद्र पचास हजार रुपए की दवाइयां सालाना भी खरीदी जाएं तो हर व्यक्ति को सालाना पचास पैसे की दवाई ही दी जा सकती है। यह इतनी कम रकम है कि किसी मरीज के लिए एक खुराक दवा भी संभव नहीं है। मुश्किल यह भी है कि हमने अब तक ग्रामीण इलाकों में तकनीकी के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए न तो कोई पहल की है और न कोई गंभीर कदम उठाए हैं।

आज जबकि गांव-गांव तक मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी जैसी तकनीकी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं तो इन्हीं की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं भी तकनीक के जरिए गांव तक भेजी जा सकती हैं। विदेशों में भी इसके कई सफल प्रयोग हुए हैं। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सबसे अहम है कर्मचारियों और डॉक्टरों की तैनाती। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्स व महिला स्वास्थ्य कर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन उपलब्ध आंकड़ों पर गौर करें तो साफ है कि स्थिति भयावह है। हमारे यहां प्रशिक्षित अमले की भी भारी कमी है। भारतीय स्वास्थ्य सूचना तंत्र के आंकड़े कहते हैं कि हमारे यहां 70 से 80 फीसद डॉक्टर और करीब 85 से 90 प्रतिशत नर्स शहरी इलाकों में काम कार्यरत हैं जबकि 80 से 90 फीसद एएनएम देहाती इलाकों में तैनात हैं। ऐसी स्थिति में साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब साढ़े बारह हजार लोगों पर एक डॉक्टर मिल पाता है। इनमें भी आदिवासी एवं दलित क्षेत्र वाले मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में स्थिति ज्यादा ही भयावह है। ये अपने पड़ोसी राज्यों से भी पिछड़े हुए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डॉक्टर-मरीज का अनुपात मानक एक हजार तय है यानी हजार लोगों पर एक डॉक्टर। लेकिन हमारे यहां यह अनुपात बेमानी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो यह आंकड़ा और भी कम हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात डॉक्टरों की संख्या वर्ष 2007 में 22 हजार 608 थी जो 2014 में बढ़ कर भी केवल 27 हजार 355 हो सकी है। शहरी क्षेत्रों में डॉक्टरों की तादाद पहले से ही ज्यादा है, उस पर नए डॉक्टर भी शहरों में ही काम करना पसंद करते हैं। ज्यादातर युवा डॉक्टर संपन्न परिवारों से आते हैं और गांवों को लेकर उनके मन में कई पूर्वाग्रह होते हैं। उनके लिए गांव बचपन से ही हेय दृष्टि लिए होता है। उन्हें अपने चमकदार कैरियर के लिए लगता है कि गांव में जाना भविष्य को खत्म कर देने जैसा है। गांव में उन्हें वह चमचमाती दुनिया नजर नहीं आती जिसके वे अभ्यस्त हो चुके होते हैं। चिकित्सा शिक्षा रोग होने के बाद उनके इलाज के लिए ही छात्रों को तैयार करती है।

सामाजिक परिस्थितियों के अध्ययन पर कोई जोर नहीं दिया जाता, जिनमें ये रोग पनपते हैं, न ही रोगमुक्त वातावरण के निर्माण के लिए ध्यान दिया जाता है। छात्रों को इतना भर बताया जाता है कि लोह तत्त्व की गोलियां, सुई या फिर विटामिन की गोलियों से इलाज किया जाए। इसी कारण वे जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने में कोई रुचि नहीं रखते जैसे लोग क्यों भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं या समय रहते इलाज करवाने क्यों नहीं पहुंच पाते। हालांकि अब पाठ्यक्रम में सामाजिक व निवारक चिकित्सा को जोड़ दिया गया है पर इसे गंभीरता से लेने वाले छात्रों की संख्या बेहद कम है। गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अब नए सिरे से समाज, सरकार और स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को प्रयास करने होंगे। उन कारकों पर भी पुनर्विचार की जरूरत है जो रोड़ा बनते हैं।

ट्विटर

अब सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकता है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकना किसी के हाथ में नहीं है। राज्य में हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।

बी. श्रीरामुलु, स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटक

कोरोना को लेकर स्थिति काबू में है। संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है।

लव अग्रवाल, स्वास्थ्य सचिव

सत्यार्थ

नफरत की आग

एक गांव में रहीम नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और मिलनसार था। गांव के लोगों की मदद के लिए वह सदैव तैयार रहता था। गांव वाले भी उसे पसंद करते थे व उसके प्रति सम्मान का भाव रखते थे। वह अपनी मेहनत से उगाई फसल को बेचकर अच्छी-खासी कमाई कर लेता था। उसी गांव में दूसरा किसान रफीक भी रहता था। रफीक और रहीम के खेत पास-पास ही थे। रफीक को यह जरा भी अच्छा नहीं लगता था कि सभी गांव वाले रहीम को अच्छा मानते हैं। वह रहीम से नफरत करता था। रहीम हमेशा अपने खेतों पर काम करता रहता था, पर रफीक यहां-वहां घूमने में ही अपना समय निकाल देता था। वह हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता था, ताकि वह रहीम को कोई नुकसान पहुंचा सके। एक बार रहीम के खेत में अच्छी फसल हुई। इससे रफीक को जलन हुई। फसल कटने से पहले ही एक दिन मौका देखकर उसने रहीम के खेत में आग लगा दी। आग फैलने लगी, तो रफीक का खेत भी जलने लगा। गांव वालों को जब यह पता चला कि रहीम के खेत में आग लगी है, तो वे जी-जान से आग बुझाने में जुट गए। रहीम की आधी फसल जलने से बच गई, लेकिन रफीक के खेत की ओर चलने वाली तेज हवा व आग ने उसकी पूरी फसल ही चौपट कर डाली। लोग चाहकर भी रफीक की मदद नहीं कर पाए। यह उसकी लगाई हुई आग का परिणाम था, जो उसे ही भुगतना पड़ा। इसका सार यह है कि हमें किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति से सीख लेते हुए खुद भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। कभी-कभी नफरत की आग का परिणाम व्यक्ति को खुद भुगतना पड़ता है, रफीक की तरह।

विरोध प्रदर्शन

सिख संगठन 'जग आसरा गुरु ओट' (जागो) पार्टी के अध्यक्ष मंजीत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को नई दिल्ली के टीन मूर्ति चौक पर आईएसआई (पाकिस्तान) और गुरपर्वत सिंह पन्नू (सिख फॉर जस्टिस) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

चाबहार रेलवे परियोजना से बाहर नहीं हुआ भारत

ईरान ने दी सफाई: फरहाद मोंतासिर ने कहा, यह खबर बिल्कुल गलत

तेहरान ■ एजेंसी

ईरान ने चाबहार-जाहेदान रेलवे परियोजना से भारत को बाहर किए जाने के दावों को खारिज किया है। एक भारतीय समाचारपत्र की रिपोर्ट में भारत को इस परियोजना से बाहर किए जाने के दावे को ईरान ने गलत बताया है। ईरान के बंदरगाहों और समुद्री संगठन के डिप्टी फरहाद मोंतासिर ने बुधवार को अल जजीरा के साथ बातचीत में कहा कि यह खबर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईरान ने भारत के साथ चाबहार-जाहेदान रेलवे परियोजना को लेकर कोई डील नहीं की है।

मोंतासिर ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ चाबहार में निवेश के लिए बस दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला बंदरगाह की मशीनरी और उपकरणों को लेकर है और दूसरा भारत का यहां 150 मिलियन डॉलर का निवेश है।

अमेरिकी प्रतिबंधों का दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं

मोंतासिर ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का चाबहार में ईरान और भारत के संबंधों और सहयोग से कोई लेना-देना नहीं है। बता दें कि 2018 में अमेरिका 2012 के ईरान स्वतंत्रता और प्रति-प्रसार अधिनियम (आईएफसीए) के तहत चाबहार बंदरगाह परियोजनाओं में छूट देने के लिए राजी हो गया था। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बंदरगाह परियोजना को ईरान के आर्थिक भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया था। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल ने इस परियोजना के लिए हर सेवा और फंड देने की बात कही है। जानकारी के अनुसार, कंपनी परियोजना में लगभग 1.6 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी।

न्यूज

'गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल'12 को होगी रिलीज

मुंबई, (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की आने वाली फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल'12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म को लेकर काफी चर्चा में है। जाह्नवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म से जुड़ा अपना एक लुक शेयर कर बताया है कि उनकी ये फिल्म 12 अगस्त को रिलीज होगी। जाह्नवी कपूर ने फिल्म की रिलीज डेट के साथ लिखा, ''कारगिल युद्ध में भारत की पहली महिला वायु सेना अधिकारी की कहानी आपके सामने लाते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उम्मीद है कि ये जर्नी मेरी तरह आपको भी काफी प्रभावित करेगी।

असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 36 लाख लोग प्रभावित

गुवाहटी, (एजेंसी)। असम में पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर जारी भारी बारिश से राज्य में भीषण बाढ़ के हालात बन गए हैं और इसकी चपेट में आने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से गुरुवार सुबह जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार शाम को बाढ़ से दो और लोगों की मौत के बाद राज्य में बाढ़ की चपेट में आ कर मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई हैं। विभाग के अनुसार बाढ़ से अब तक 36,42,546 लोग प्रभावित हुए है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आश्रय प्रदान करने के लिए कई जिलों में 247 राहत शिविर बनाए गए हैं।

ब्राजील के राष्ट्रपति जायर पुन: पॉजिटिव पाए गए

ब्रासीलिया, (एजेंसी)। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे इससे एक सप्ताह पहले भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वे लोग मेरी एक नई जांच करेंगे। सबकुछ ठीक होगा और हम लोग सामान्य काम-काज पर लौट सकते हैं। बोल्सोनारो राजधानी ब्रासीलिया स्थित अल्वोराडा पैलेस में हैं और उनके साथ चिकित्सकों की एक टीम है।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे! कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं। कोरोना को धोना हैं।

शोधकर्ताओं को मिली बड़ी कामयाबी

न्यूयॉर्क में वैज्ञानिकों ने खराब फेफड़ों को 24 घंटे में दोबारा किया जिंदा

न्यूयॉर्क ■ एजेंसी

फेफड़ों की बीमारी मानी जा रही कोरोना के बीच वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कुछ वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के खराब हो जाने के बाद भी उन्हें स्वस्थ करने का तरीका खोज निकाला है।

शोधकर्ताओं ने यह तकनीक ब्रेन-डेड (मस्तिष्क मृत) मरीजों से मिले छह खराब फेफड़ों पर आजमाई थी। फेफड़ों को रेस्पिरेटर यंत्र से जोड़कर इनमें सूअर का रक्त प्रवाहित किया, जिससे ये 24 घंटों में ही 'जिंदा' हो उठे। इस सफलता के बाद इंसानों में यह प्रयोग किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी दान में मिले अधिकांश फेफड़े चंद घंटों में खराब हो जाते हैं। नई कामयाबी के बाद अब पहले से ज्यादा फेफड़े प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध रहेंगे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फेफड़ा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. जैकरी एन कोन का कहना है कि यह एक परिवर्तनकारी विचार है, जिससे मरीजों की जान बचेगी।

ये प्रयोग विज्ञान की कल्पना जैसा

नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित शोध के परिणाम को विज्ञान की कल्पना (साइंस फिक्शन) माना जा रहा है। कोलंबिया और वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता पिछले आठ साल से खराब फेफड़ों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। ताजा शोध में उन्होंने हरेक फेफड़े को 'सांस' देने के लिए प्लास्टिक के अलग-अलग बक्से में रखकर एक रेस्पिरेटर से जोड़ा था। फिर इन्हें जिंदा सूअर के गले की बड़ी नलिका से जोड़ दिया, जिससे उसका रक्त वाहिकाओं के जरिए फेफड़ों में बहने लगा। फिर एक दिन में ही ये बेकार फेफड़े बेहतर हो गए और प्रयोगशाला में पूर्ण स्वस्थ पाए गए।

इंसानों में इस तरह होगा इस्तेमाल

इस तकनीक को एक्स वीवो लंग पर्फ्यूजन (ईवीएलपी) नाम दिया है, जिसका प्रयोग अब इंसानों पर होगा। इसके तहत मरीज के गले में बड़ा कैथेटर डालकर फेफड़े में रक्त प्रवाहित किया जाएगा। फेफड़े का संपर्क कमरे में रखे रेस्पिरेटर से होगा। अमेरिकी लंग एसोसिएशन के मुताबिक, दान में मिले सिर्फ 28 फीसदी फेफड़े ही इस्तेमाल हो पाते हैं बाकी खराब हो जाते हैं। शोध में शामिल वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के डॉ. मैथ्यू डब्ल्यू बशेटा के मुताबिक, अगर दान किए 40 फीसदी फेफड़े भी प्रत्यारोपित हो पाएं तो काफी मरीजों को प्रतीक्षा सूची में नहीं रहना पड़ेगा।

भारतीय नागरिकों ने एच-1बी वीजा के खिलाफ दायर किया मुकदमा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। एच-1बी वीजा पर हाल में आए एक शासकीय आदेश के खिलाफ सात नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिकों के एक समूह ने मुकदमा दायर किया है। इस आदेश के तहत उनके अमेरिका में प्रवेश पर रोक लग सकती है अथवा उन्हें वीजा जारी नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत के न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन ने बुधवार को विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और होमलैंड सुरक्षा विभाग के कार्यकारी मंत्री चाड एफ वोल्फ के साथ श्रम मंत्री युजिन स्कालिया को सम्मन जारी किए।

यह मुकदमा मंगलवार को अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत में दायर किया गया। वकील वास्डेन बैनियास ने 174 भारतीय नागरिकों की ओर से दायर मुकदमे में कहा कि एच-1बी/एच-4 वीजा पर प्रतिबंध का शासकीय आदेश अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, परिवारों को अलग करता है और कांग्रेस को खारिज करता है।

इस मुकदमे में एच-1बी या एच-4 वीजा जारी करने पर पाबंदी लगाने या नए एच-1बी वीजा धारकों को देश में प्रवेश करने से रोकने वाले शासकीय आदेश को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह विदेश विभाग को एच-1बी और एच-4 वीजा के लिए लंबित अनुरोधों पर फैसले देने के लिए निर्देश जारी करे। गौरतलब है कि ट्रंप ने 22 जून को शासकीय आदेश जारी कर इस साल के अंत तक एच-1बी कार्य वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी।

जो बिडेन, ओबामा, बिल गेट्स समेत कई बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल जो बिडेन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट गुरुवार को हैक कर लिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह एक बिटकॉइन घोटाला प्रतीत हो रहा है।

अफसरों ने जताई बिटकॉइन घोटाले की आशंका

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार केन वेस्ट के आधिकारिक खातों को भी निशाना बनाया गया था। इन अकाउंट से कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में दान करने को कहा गया था। बिल गेट्स के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया कि हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता रहा है और अब वह समय आ गया है। आप मुझे एक हजार डॉलर भेजिए मैं आपको दो हजार डॉलर वापस भेजूंगा।

इन अकाउंट से किए गए ट्वीट कुछ मिनट में डिलीट हो गए। ट्विटर पर सभी ब्लूटिक वाले अकाउंट से किसी भी तरह के ट्वीट नहीं किए जा सकेंगे और पासवर्ड भी रीसेट नहीं किए जा सकेंगे। ट्विटर ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है और इससे संबंधित जानकारी जल्द ही दी जाएगी।

भीमा कोरेगांव केस के अभियुक्त कोरोना पॉजिटिव

मुंबई, (एजेंसी)। कवि, लेखक और 2018 भीमा कोरेगांव केस के आरोपी और जेल में बंद कवि-कार्यकर्ता वरवरा राव के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अस्पताल प्रशासन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। न्यायिक हिरासत में नवी मुंबई के तालोजा जेल में बंद 80 वर्षीय राव को इसी सप्ताह सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जेजे अस्पताल के डीन डॉक्टर रंजीत मनकेश्वर के अनुसार, राव की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें उनके संक्रमित की पुष्टि हुई है। उनका इलाज चल रहा है। चक्कर आने की शिकायत होने पर राव को अस्पताल में भर्ती कराया था। उनके परिवार ने उनकी बिगड़ती हालत पर चिंता जताई थी। शनिवार को फोन रिसीव करने के बाद पत्नी हेमलता, बेटी सहाजा, अनाला और पवाना ने संवाददाताओं के समक्ष उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी।

विश्व में कोरोना से 1.37 करोड़ संक्रमित, 5.87 लाख की मौत

बीजिंग/जिनेवा/नई दिल्ली(एजेंसी)। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और दुनियाभर में इससे संक्रमित लोगों की संख्या 1.37 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 5.87 लाख से अधिक लोगों की इसके कारण मौत हुई है। कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर हैं। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है जबकि भारत मृतकों की संख्या के मामले में आठवें स्थान पर है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र (सीएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,37,38,708 हो गई है, जबकि इसके कारण 5,87,904 लोगों ने जान गंवाई है।

अमेरिका में कोरोना से 36,18,739 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 1,40,185 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 19,72,072 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 75568 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 32695 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 9,76,826 हो गई है। वहीं इस दौरान 606 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 25,020 हो गई है।संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। देश में 612815 रोगमुक्त हो चुके हैं।

अमेरिका: गोकाडा एप के सीईओ का शव अपार्टमेंट में मिला, जांच जारी

वाशिंगटन, (एजेंसी)। राइडिंग हेलिंग एप गोकाडा के सीईओ फहीम सालेह का शव उनके न्यूयॉर्क स्थित लक्जरी अपार्टमेंट मिला है।

न्यूयॉर्क पुलिस की प्रवक्ता ने कहा कि 33 वर्षीय फहीम सालेह मंगलवार को अपने मैनहेटन स्थित घर में मृत पाए गए। सालेह के शव को टुकड़े-टुकड़े करके अलग-अलग रखा गया था। शव को देखकर लग रहा है कि उनकी हत्या यहीं की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में जांच जारी है। हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जासूसों को सालेह के शव के पास एक इलेक्ट्रिक आरी मिली। उनका सिर और शरीर का बाकी हिस्सा अपार्टमेंट में कहीं और पाए गए थे। सालेह की बहन को उनका शव दिखा और फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी।

डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में पिछड़ने की अटकलें, अभियान प्रबंधक ब्राड पार्स्केल को हटाया

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका में कोरोना वायरस (कोविड-19) कहर के बीच नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार जो बिडेन से पिछड़ने की अटकलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान प्रबंधक ब्राड पार्स्केल को हटाकर बिल स्टेपियन को नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है।

श्री ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बिल स्टेपियन को ट्रंप प्रचार अभियान के प्रबंधक की भूमिका दी गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत लंबे वक्त तक मेरे साथ रहे और हमारी शानदार डिजिटल एवं डेटा रणनीतियों की अगुवाई करने वाले ब्राड पार्स्केल प्रचार अभियान के वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर यह भूमिका निभाते रहेंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों 2016 की हमारी ऐतिहासिक जीत में शामिल रहे और मैं एक साथ मिलकर बहुत बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण दूसरी जीत के लिए उत्साहित हूं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार की जीत बहुत आसान होनी चाहिए, क्योंकि हमारे चुनावी नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, टीका और इलाज जल्द ही सामने होंगे और अमेरिकी सुरक्षित सड़कें और समुदाय चाहते हैं।

भारतीयों में नेपाल के प्रति कोई दुर्भावना नहीं हो सकती: विहिप

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भगवान राम के नेपाल में जन्म लेने वाले केपी शर्मा ओली के बयान पर कंप्यूटर बाबा द्वारा भारत में रह रहे नेपाली लोगों को खदेड़ने की बात पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने चिंता जताई है। विहिप के महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि नेपाल का हिंदू भी राम भक्त है और इसीलिए हिंदुओं में वहां के लोगों के लिए कोई गलत भावना नहीं हो सकती। मिलिंद परांडे ने भारत मे रहने वाले नेपालियों को लेकर दिए गए कंप्यूटर बाबा के बयान की निंदा की।

उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा के भारत में रहने वाले नेपालियों के विषय में दिया गया बयान बेहद निंदनीय है। नेपाल का हिंदू समाज अयोध्या एवं श्रीराम भक्त है। अतः भारत के संपूर्ण हिंदू समाज के मन में नेपाल या नेपालियों के प्रति कोई दुर्भावना हो ही नहीं सकती। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और षडदर्शन समिति के अध्यक्ष महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर जमकर निशाना साधा था।

दुबे के साथियों की तलाश तेज, पत्नियों से पूछताछ

कानपुर, (एजेंसी)। यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे के मारे जाने के बाद पुलिस ने अब उसके फरार साथियों की खोज तेज कर दी है। जहां भी उनके होने की संभावना है, वहां पुलिस दबिश दे रही है। विकास दुबे के ममरे भाई शशिकांत पांडेय की पत्नी मनु उर्फ पिंकी के तीन कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद पुलिस फरार चल रहे बदमाशों की पत्नियों के मोबाइल चेक कर रही है।

पुलिस ने शशिकांत की पत्नी की भूमिका संदिग्ध मिलने के बाद आठ पुलिसकर्मियों की हत्या में फरार अन्य आरोपितों के घर में दोबारा छापेमारी की। उनके घर में मौजूद महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी है। सभी के मोबाइल जांच के लिए कब्जे में लिए हैं। कॉल डिटेल चेक की जा रही है। अगर आरोपितों की मदद में उनकी संलिप्तता मिली तो उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। शशिकांत पांडेय की पत्नी मनु उर्फ पिंकी जांच के दायरे में आ गई है। पुलिस ने उससे घंटों पूछताछ की, लेकिन सास की तबीयत खराब होने के चलते हिरासत में नहीं लिया।

रोमांच

आसमान में अद्भुत नजारा देख रोमांचित हैं खगोल शास्त्री

अरसे बाद उत्तरी गोलार्द्ध में नजर आ रहा है धूमकेतु

जम्मू ■ एजेंसी

खगोल शास्त्र में दिलचस्पी रखने वाले इन दिनों पुच्छल तारे का रोमांच देख रहे हैं। अरसे बाद उत्तरी गोलार्द्ध में पुच्छल तारा यानी धूमकेतु नजर आ रहा है। आसमान साफ होने पर यह लगभग रोजाना तड़के उत्तर पूर्व दिशा में दिखाई दे रहा है। इस पुच्छल तारे को कॉमेट नियोवाइज सी/2020 एफ3 नाम दिया गया है। दुनिया भर में लोग पुच्छल तारे की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं।

लोग तस्वीरों को सोशल मीडिया पर कर रहे हैं शेयर

लद्दाख में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की हनले स्थित आब्जर्वेटरी के प्रभारी दोरजे अंगचुक के अनुसार पुच्छल तारों को अमूमन टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकता है, ज्यादातर कॉमेट दक्षिणी गोलार्द्ध में नजर आते हैं। लंबे अरसे बाद उत्तरी गोलार्द्ध में चमकदार कॉमेट नजर आ रहा है, जिसे बिना कैमरे या टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। यह रोमांचित करने वाली घटना है। 23 जुलाई को कॉमेट नियोवाइज पृथ्वी पर सबसे नजदीक होगा। फिलहाल यह तड़के ही नजर आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे यह तारा शाम को भी नजर आने लगेगा। लिहाजा खगोल शास्त्र से जुड़े लोग इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

दुबई के अस्पताल में भारतीय का डेढ़ करोड़ का बिल माफ

हैदराबाद, (एजेंसी)। दुबई के एक अस्पताल ने मानवीय आधार पर तेलंगाना के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का भारतीय मुद्रा में 1.52 करोड़ का बिल माफ कर दिया। अस्पताल ने उसे एक पैसा वसूल किए बिना 80 दिनों के उपचार के बाद छुट्टी दे दी। तेलंगाना सरकार में एनआरआई सेल के वरिष्ठ अधिकारी ई चिट्टी बाबू के अनुसार, बुधवार को तड़के हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर, जगीतियल जिले के गोलापल्ली मंडल के वेणुगुमटला गांव के निवासी 42 वर्षीय ओडनला राजेश आए।

चिट्टी बाबू ने बताया कि हमने उनके परिवार के सदस्यों के साथ उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। हमने उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में जाने की इजाजत देते हुए उनके पैतृक गांव भेज दिया। राजेश की पत्नी लक्ष्मी पेशे से धोबी हैं और दैनिक मजदूरी पर एक किसान के रूप में भी काम करती हैं। उनकी बेटी मोनिका (18) बी-कॉम की छात्रा है और उनका बेटा मधु (16) 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट) में पढ़ रहा है।

मास्क और सैनेटाईज़र का अधिक भाव वसूलने वालों को किया गया 15,34,000 रुपये का जुर्माना

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के उपभोक्ता मामले के विभाग के लीगल मैटरोलोजी विंग के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य के लोगों को मास्क और सैनेटाईज़र निश्चित भाव पर मुहैया करवाने के मकसद से राज्य भर में 1806 दुकानों और कैमिस्ट दुकानों पर छापे मारे गए। इनमें से 472 व्यापारिक संस्थानें अधिक कीमत वसूलती पायी गई, जिनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुये इनको 15,34,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। यह जानकारी आज यहाँ विभाग के प्रवक्ता ने दी।

प्रवक्ता ने बताया कि वस्तुओं की अधिक कीमत वसूलने सम्बन्धी उनके विभाग को 17 शिकायतें मिली थीं, जिन पर कार्यवाही करते हुये राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसके दौरान 227 दुकानदारों पर अधिक कीमत वसूल करने पर पी.सी.आर.एक्ट और अन्य सम्बन्धित धाराओं के अधीन मामले दर्ज किये गए। इसके अलावा 245 दुकानदारों को पी.सी.आर.एक्ट और अन्य सम्बन्धित धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज करके जुर्माना किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा डी.जी.पी. को कोविड के लिए विशेष दस्ते तैयार करने के आदेश, पुलिसकर्मियों को गैर-जरूरी ड्यूटियों से हटाया जाए

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के आदेश, स्वास्थ्य विभाग को रोकथाम सम्बन्धी कड़े कदम उठाने के निर्देश

चंडीगढ़/ब्यूरो

राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और मौतों के मद्देनज़र पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने गुरूवार को राज्य के डी.जी.पी. को विशेष आरक्षित दस्ते तैयार करने के आदेश दिए हैं और इस मकसद हेतु अगले कुछ महीनों के लिए गैर-ज़रूरी ड्यूटियों पर तैनात पुलिसकर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोविड की समीक्षा सम्बन्धी एक मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को यह भी निर्देश दिए कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों ख़ासकर मास्क न पहनने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कदम उठाए जाएँ। उन्होंने डी.जी.पी. को यह निर्देश भी दिए कि कोविड के मामलों की बहुतायत वाले शहरों के एस.एस.पीज को यह हिदायतें भी दी जाएँ कि इस महामारी के और फैलाव को रोकने के लिए नियमों और सरकार द्वारा लगाई गईं पाबंदियों की सख़्ती से पालना यकीनी बनाई जाए।

पंजाब में प्रति मिलियन के हिसाब से मौतों का संख्या 7.7 प्रति मिलियन तक बढ़ने के मद्देनज़र कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि कंटेनमैंट और माईक्रो कंटेनमैंट ज़ोनों की पहचान जल्द से जल्द की जाए और इस महामारी के फैलाव को रोकने सम्बन्धी तेजीसे कदम उठाए जाएँ। राज्य में मौजूदा समय में 12 ज़िलों में 38 माईक्रो कंटेनमैंट ज़ोन हैं, जबकि छह ज़िलों में सात कंटेनमैंट ज़ोन हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा पहले से निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार टेस्टिंग बढ़ाने के लिए तुरंत कार्यवाही किए जाने पर भी जोर दिया। बेहद सावधानी बरतने बरती जाने की अहमीयत को दर्शाते हुए, हालाँकि राज्य के आंकड़े राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासनों को कहा कि ताज़ा दिशा-निर्देशों को ख़ासकर भीड़ में पाँच व्यक्तियों से अधिक को एकत्र होने की बन्दिश के संदर्भ में सख़्ती से लागू किए जाएँ।

कोविड के ख़िलाफ़ जंग जीतने के लिए लोगों से सहयोग की माँग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम ज़िला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कोविड के फैलाव को रोकने के लिए समूचे तौर पर एक मुहिम शुरु की जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि अमृतसर में ज़िला प्रशासन, पुलिस, सरकारी मैडीकल कॉलेज, कम्युनिटी मैडिसन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विशेषज्ञों द्वारा किए काम के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

उन्होंने प्राईवेट संस्थानों जैसे कि डी.एम.सी. लुधियाना द्वारा किए जा रहे काम की भी सराहना की, जिन्होंने राम श्रीराम सोसाइटी के साथ तालमेल करके लेवल-1 के मरीज़ों के लिए और ज्यादा बैड्ज़ का इंतज़ाम किया है।

उन्होंने इस काम में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए डी.सी. लुधियाना और कमिशनर ऑफ पुलिस लुधियाना की भी सराहना की।

इससे पहले डी.जी.पी. ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन उल्लंघनकर्ताओं में से 40 प्रतिशत रोज़ाना के मुसाफिर हैं।

उन्होंने बताया कि कार्यवाही करने के साथ-साथ सभी पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस फोर्स में इस समय में कोविड के 125 सक्रिय मामले हैं और इनके परिवारिक सदस्यों में से 161 सदस्यों का टैस्ट भी पॉज़िटिव पाया गया।

उन्होंने बताया कि संक्रमण से प्रभावित सभी मुलाज़िमों को एकांतवास में रखा जा रहा है।

इससे पहले विशेषज्ञ कमेटी के प्रमुख डॉ. के.के. तलवार, जो राज्य सरकार को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ कमेटी के प्रमुख हैं, ने कमेटी की कार्यवाही रिपोर्ट में खुलासा किया कि होम क्वारंटाइन / घरेलू एकांतवास मामलों की टेली-मोनिटरिंग के लिए पंजाब हैल्थ सिस्टम कोर्पोरेशन (पी.एच.एस.सी.) द्वारा टैंडर जारी कर दिए हैं और बिड्ज़ शुक्रवार तक सौंपनी होंगी।

इसी तरह पी.एच. एस.सी. द्वारा 17 ए.एल.एस. ऐंबूलैंसें मंगाने के आदेश दिए गए और इस हफ़्ते के अंत तक 5 एंबुलेंस मिलने की आशा है।

मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में प्लाज्मा बैंकों की स्थापना पर अमल सम्बन्धी डॉ. तलवाड़ ने बताया कि ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन मैडिसन, पी.जी.आई., चंडीगढ़ के पूर्व प्रमुख डॉ. नीलिमा मरवाहा को इन बैंकों की निगरानी करने का ज़िम्मा दे दिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि ए.डी.जी.पी. जेलों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत कोविड पॉज़िटिव कैदियों को 17 दिनों के लिए आईसोलेशन की सुविधाओं में रखने का फैसला लिया गया है।

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पौष्टिक मिड-डे मील मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध-विजय इंदर सिंगला

विद्यार्थियों को पौष्टिक खुराक मुहैया करवाने को यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार ने जरुरी फंड और खुराक का वितरण किया

चंडीगढ़/ब्यूरो

शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने गुरूवार को कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाब के बच्चों के सर्वपक्षीय विकास के लिए वचनबद्ध है और मिड -डे मील का खाना लगातार स्कूलों के 15.79 लाख विद्यार्थियों को मुहैया करवा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण चाहे यह यत्न प्रभावित हुए परन्तु अध्यापकों की समर्पण भावना और मेहनत सदका ऐसी संकटकालीन घड़ी में भी यह सब संभव हो सका।

श्री सिंगला ने सरकार के यत्नों की सराहना करते हुये कहा कि महामारी के कारण बहुत सी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद अध्यापक ऑनलाइन क्लासें लेने, अनाज के अलावा किताबें बाँटने में वास्तव में श्लाघायोग्य काम कर रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अकादमिक सैशन 2020 -21 की पहले वित्तीय तिमाही के लिए विद्यार्थियों को सीलबंद पैकटों में चावल और गेहूँ पहुँचाने के लिए स्कूलों को 8262.23 मीट्रिक टन खाना भेजा गया है। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही (20 जुलाई से 20 सितम्बर) के लिए, 11,974 मीट्रिक टन के वितरण को मंजूरी दी गई है।

श्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पहले ही 37.26 करोड़ रुपए के खाना पकाने की मंजूरी दी जा चुकी है जिसको केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लाभपात्री विद्यार्थियों के खातों में तबदील किया जाना था। कुछ विद्यार्थियों के पास चालू बैंक खाता न होने के कारण स्कूलों के पास लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि पड़ी है।

श्री सिंगला ने इस मामले का गंभीर नोटिस लेते हुये शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत की थी कि वह लाभपात्री विद्यार्थियों के लिए खाना पकाने सम्बन्धी रकम जारी करने के लिए मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय से मंजूरी लें। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई, 2020 को भारत सरकार को एक लिखित पत्र भी भेजा गया है जिसमें विद्यार्थियों को खाना पकाने की लागत की नकद अदायगी की इजाजत माँगी गई है परन्तु अभी जवाब का इन्तजार है।

उन्होंने बताया कि मैं यह मसला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री के पास निजी तौर पर भी उठाया है और सरकारी स्कूली विद्यार्थियों की हितों के लिए जल्द ही इसका उपयुक्त हल निकाल लिया जायेगा। कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिया कि एक बार जब हमें मंजूरी मिल गई तो कुछ दिनों के अंदर ही खाना पकाने की लागत विद्यार्थियों को नकद दे दी जायेगी।

पंजाब सरकार ने कोविड के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के लिए उपचार दरें निर्धारित की

चंडीगढ़/ब्यूरो

कोरोना महामारी के चलते निजी अस्पतालों द्वारा मुनाफ़ाख़ोरी किए जाने पर रोक लगाने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने कोविड के इलाज के लिए खर्चे की हद निर्धारित कर दी है।

इस फ़ैसले का ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोविड सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा करने के बाद में किया गया।

उपचार सम्बन्धी यह दरें डॉक्टर के.के. तलवार कमेटी द्वारा निजी अस्पतालों और मैडीकल कॉलेजों सम्बन्धी निर्धारित की गई हैं और इनके अंतर्गत आईसोलेशन बैड्ज़, आई.सी.यू. में इलाज, अस्पताल में दाख़िल होने के खर्च और दाख़िल होने के बाद प्रतिदिन के खर्चे शामिल हैं।

साधारण बुख़ार जिसमें आईसोलेशन बैड्ज़ की जरूरत पड़ती हो और जिसमें देख-रेख और ऑक्सीजन भी शामिल हो, के लिए दाख़िल होने के बाद प्रतिदिन के खर्चे सभी निजी मैडीकल कॉलेजों / एन.बी.ई. के टीचिंग प्रोग्राम वाले एन.ए.बी.एच. निजी अस्पतालों के लिए 10,000 रुपए के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं, जबकि एन.ए.बी.एच. से मान्यता प्राप्त अस्पतालों (निजी मैडीकल कॉलेजों जिनमें पी.जी. / डी.एन.बी. कोर्स नहीं हैं समेत) अस्पतालों के लिए 9,000 रुपए और एन.ए.बी.एच. से गैर-मंज़ूरशुदा अस्पतालों के लिए 8,000 रुपए के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं।

इन श्रेणियों के अस्पतालों के लिए गंभीर बुख़ार (वेंटिलेटर की ज़रूरत के बिना आई.सी.यू.) के लिए क्रमवार 15 हजार, 14 हजार और 13 हज़ार रुपए तक की सीमा निर्धारित की गई है, जबकि बहुत ही नाज़ुक स्थिति वाले मरीज़ों के लिए यह दरें क्रमवार 18 हज़ार, 16500 और 15 हज़ार निर्धारित की गई हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी कीमतों में पी.पी.ई. की कीमत भी शामिल की गई है।

निजी अस्पतालों को मामूली बुख़ार के मामलों के इलाज के लिए प्रोत्साहन देने हेतु डॉ. तलवार कमेटी ने ऐसे मामलों के लिए प्रतिदिन दाख़िला फीस क्रमवार 6500 रुपए, 5500 रुपए और 4500 रुपए निर्धारित की है। सरकार द्वारा यह कदम कोविड के इलाज सम्बन्धी निजी अस्पतालों द्वारा वसूल किए जाने वाले उपचार खर्च सीमा से अधिक लिए जाने के बाद उठाया गया है।

मुख्यमंत्री को निजी तौर पर इस सम्बन्धी शिकायतें मिली थीं और उन्होंने डॉ. तलवार कमेटी और राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को इस मामले की तरफ ध्यान देने और निजी अस्पतालों के साथ बातचीत करने के बाद वाजिब उपचार दरें निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंजाब सरकार ने हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निर्देशक श्री सुनील वशिष्ठ को राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया

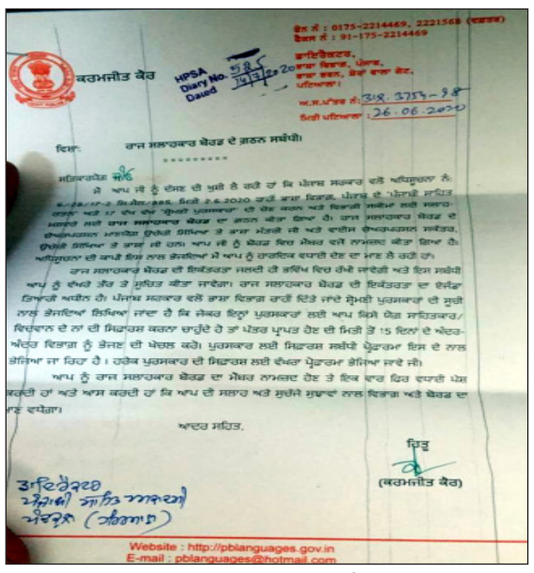

जालंधर ब्रीज ब्यूरो

यह पूरे हरियाणा के साहित्यिक जगत के लिए एक बड़े सम्मान की बात है कि भाषा विभाग, (पंजाब सरकार) ने हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निर्देशक श्री सुनील वशिष्ठ जी को राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस खुशी के मौके पर हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी और हरियाणा के साहित्य प्रेमियों द्वारा पंजाब सरकार का धन्यवाद किया गया।

मंत्री व विधायकों के गनमैनों को विधानसभा में नहीं मिलेगा प्रवेश

कोरोना से बचाव के लिए सत्र के दौरान दिखेंगे कई बदलाव

नई दिल्ली/ब्यूरो

विधानसभा सत्र में इस बार बीमारी से बचाव के लिए कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मंत्री और विधायकों के गनमैनों को विधानसभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। हर प्रवेश द्वार पर डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के पावस सत्र में कोरोना से बचने के लिए अनेक सावधानियां बरती जाएगी। जिन विधायकों और मंत्रियों के साथ गनमैन विधानसभा परिसर तक पहुंचते थे। इस बार उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाएगा। विधानसभा के अधिकारियों का कहना है कि यदि विशेष आवश्यकता पड़ी तो मंत्री के निजी सचिव को अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। विधानसभा के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। यहां पर अंदर प्रवेश करने वाले मंत्री और विधायकों की प्रतिदिन कोरोना स्क्रीनिंग होगी। इस दौरान यदि किसी में कोरोना संक्रमण के लक्षण प पाए जाते हैं तो फिर उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। सत्र में सभी दीर्घा बंद रहेगी। दर्शक के तौर पर इस बार किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मंत्रियों और विधायकों के साथ उनके क्षेत्र से आने वाले लोग यदि विधानसभा आते हैं तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन होगा। विधानसभा में जिस कुर्सी पर तीन सदस्य बैठते रहे हैं। उसमें से एक सदस्य को वहां से अलग किया जाएगा। ऐसे सदस्य के बैठने की व्यवस्था प्रथक से की जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना रहे। सदन में प्रत्येक सदस्य को मास्क लगाकर आना होगा। यदि किसी विधायक या मंत्री के पास मास्क नहीं हैं। तो गेट पर डॉक्टरों की टीम उन्हें मास्क उपलध कराएगी।

सदन को प्रतिदिन दो बार किया जाएगा सैनिटाइज : एपी सिंह

विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि सत्र के दौरान विधानसभा को दो बार सैनिटाइज किया जाएगा। सदन शुरू होने के पहले और बाद में सैनिटाइज की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया है कि विधानसभा परिसर में इस बार कवरेज के लिए मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्री सिंह का कहना है कि दूरदर्शन, एएनआई, पीटीआई एवं जनसंपर्क के माध्यम से मीडिया को विधानसभा का कवरेज उपलध कराया जाएगा। श्री सिंह का कहना है कि प्रवेश द्वार पर हर सदस्य की प्रतिदिन स्क्रीनिंग होगी। उन्होंने बताया है कि इस बार मंत्री और विधायक के साथ आने वाले गनमैन को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाएगा। ताकि विधानसभा के अंदर लोगों की ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो पाए।

पूरे देश में बिहार के गोपालगंज का पुल टूटने की खबर वायरल

उद्घाटन के 29 दिन बाद बहा 265 करोड़ से बना हुआ पुल

पटना/ब्यूरो

बिहार में भारी बारिश और बाढ़ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के दावे की पोल खोल कर रख दी है। बिहार के गोपालगंज के सत्तरघाट इलाके में जिस पुल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महज 29 दिन पहले किया, वो बाढ़ के पानी में बह गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। यह पुल आठ साल से बन रहा था और इसे बनाने में 265 करोड़ की लागत आई है। पुल बहने की घटना के बाद आजेडी और कांग्रेस नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं सत्ताधारी जेडीयू का कहना है कि पानी का बहावर इतना ज्यादा था कि पुल बह गया। पुल को बनाने के दौरान गुणवत्ता में कोई कमी नहीं की गई। जो हिस्सा पानी में बहा है, वो पुल से जोड़ता है जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। अप्रोच रोड बह जाने से गांव वाले अब पुल तक पहुंचने में असमर्थ हो गए हैं। आरजेडी मुखिया तेजस्वी यादव ने घटना को लेकर तंज कसते हुए हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 8 वर्ष में 263.47 करोड़ से निर्मित गोपालगंज के सत्तरघाट पुल का 16 जून को नीतीश जी ने उद्घाटन किया था, आज 29 दिन बाद यह ध्वस्त हो गया। खबरदार! अगर किसी ने इसे नीतीश जी का भ्रष्टाचार कहा तो? 263 करोड़ तो सुशासनी मुंह दिखाई है।

मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान 9.5 लाख किसान परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन लाने के लिए दी गई हरी झंडी

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने 9.50 लाख किसानों और उनके परिवारों को साल 2020-21 के लिए 'आयूष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना' के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमे का लाभ देने के लिए हरी झंडी दे दी है, जबकि बीते वर्ष पाँच लाख किसानों को इस स्कीम में शामिल किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा यह स्कीम 20 अगस्त, 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर शुरू की गई थी और साल 2019-20 के दौरान 45 लाख परिवारों को इस योजना के दायरे के अधीन लाया गया, जो ख़ासकर कोविड संकट के दौरान पंजाब के लोगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई। राज्य सरकार ने 'आयूष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना' के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए दरें भी तय की गईं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभपात्री दिल के ऑपरेशन, कैंसर के इलाज, जोड़ बदलवाने और एक्सीडेंट के मामलों जैसे बड़े ऑपरेशनों के इलाज समेत 1396 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पतालों और 208 सरकारी अस्पतालों में पाँच लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के पहले साल के दौरान पाँच लाख किसान इस योजना के दायरे के अधीन आए थे, जिनको मंडी बोर्ड द्वारा साल 2015 में जारी किए गए 'जे' फॉर्मों के आधार पर योग्य पाया गया था। साल 2020-21 के दौरान 8.70 लाख 'जे' फॉर्म होल्डर किसानों और 80,000 गन्ना उत्पादकों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मंडी बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 2020 को और उसके बाद 8.70 लाख किसानों को उनकी कृषि उपज बेचने के लिए 'जे' फॉर्म होल्डरों के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है और इसी तरह 1 नवंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 के पिड़ाई सीजन के दौरान गन्ने की फ़सल बेचने वाले 80,000 गन्ना उत्पादक हैं, जो इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा इनको स्कीम में शामिल करने के साथ सभी 9.50 लाख किसान और उनके परिवार 20 अगस्त, 2020 से योजना का लाभ लेने के हकदार बन जाएंगे।

पिछले साल स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल थे 5 लाख किसान

मंडी बोर्ड ने किसानों से 24 जुलाई तक आवेदन माँगे, गन्ना किसानों को भी मिलेगा लाभ

मंडी बोर्ड द्वारा किसानों के बीमे का समूचा प्रीमियम अदा किया जाएगा, जिनको साल भर के लिए पाँच लाख रुपए का नगदी रहित इलाज मुहैया होगा। 'जे' फॉर्म और 'गन्ना तोल पर्ची' वाले सभी योग्य किसानों को 24 जुलाई तक घोषणा पत्र ज़रुरी दस्तावेज़ों समेत सम्बन्धित मार्केट कमेटी कार्यालय या आढ़तिए के पास जमा करवाने होंगे।

मुख्यमंत्री ने पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह को बिना किसी दिक्कत के इस सुविधा का लाभ लेने को यकीनी बनाने में किसानों की सहायता करने के लिए मार्केट कमेटियों को ज़रूरी हिदायतें जारी करने के लिए कहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास अनिरुद्ध तिवाड़ी ने बताया कि मंडी बोर्ड ने योग्य किसानों से आवेदनों की माँग की है, जिससे हरेक किसान को इसका लाभ मुहैया करवाना यकीनी बनाया जा सके। इच्छुक किसानों द्वारा स्वै-घोषणा पत्र वाला फॉर्म सम्बन्धित मार्केट कमेटी कार्यालय या आढ़तिया फर्म से प्राप्त किया जा सकता है या फिर पंजाब मंडी बोर्ड की वैबसाईट www.mandibàæard.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। मंडी बोर्ड द्वारा किसानों से आवेदन प्राप्त होने के बाद विशेष तौर पर बनाए गए पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद योग्य किसानों को 'स्वास्थ्य बीमा कार्ड' जारी हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस नगदी रहित स्कीम के साथ सभी बीमारियाँ जिनमें 24 घंटे से अधिक समय के लिए अस्पताल में दाख़िल होने की ज़रूरत होती है या दिन के समय देखभाल के साथ इलाज संबंधी योजना के अधीन सूचीबद्ध हैं, का इलाज होगा। श्री तिवाड़ी ने आगे बताया कि इस बीमा योजना के अंतर्गत किसान परिवार में घर के प्रमुख के अलावा पति / पत्नी, माता / पिता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी और उसके नाबालिग बच्चे, विधवा बहु और उसके नाबालिग बच्चे लाभ के हकदार माने जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आगे बताया कि इस सम्बन्धी कोई भी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.